



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255]
No. 255]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 1997/चैत्र 27, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1997/CHAITRA 27, 1919

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1997

का. आ. 332 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 43-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन विद्युत मंत्रालय तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 251 (अ), दिनांक 30 मार्च, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

पैरा (क) में धारा 1.5 में निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी, अर्थात् :—

“टिप्पणी—यदि कोई उत्पादन कंपनी भूमि को पट्टे पर लेती है तो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा निर्धारित पट्टेदारी शुल्क, जैसी स्थिति हो, को भूमि की नाममात्र की लागत की व्याज देयता के बदले में टैरिफ में एक छूट प्राप्त राशि के रूप में माना जा सकता है।”

[फा. सं.-6/1/टैरिफ/96/खंड-4]

राकेश कक्कड़, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना का. आ. 251 (अ), दिनांक 30 मार्च, 1992 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्या द्वारा उसमें संशोधन किया गया :—

- (1) का. आ. 36 (अ), दिनांक 19 जनवरी, 1994
- (2) का. आ. 605 (अ) दिनांक 22 अस्त, 1994
- (3) का. आ. 39 (अ) दिनांक 13 जनवरी, 1995
- (4) का. आ. 167 (अ) दिनांक 6 नवम्बर, 1995
- (5) का. आ. 151 (अ) दिनांक 26 फरवरी, 1997

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 1997

S. O. 332 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Power and Non-conventional Energy Sources No. S. O. 251 (E), dated the 30th March, 1992, namely:—

In the said notification

in clause 1.5, in paragraph (a), the following note shall be inserted, namely:—

“Note :—In case a generating company takes land on lease, the leasing charges as determined by the Central Government or the State Government or any Statutory body, as the case may be, considered as a pass through item in the tariff in lieu of interest liability of the notional cost of the land”.

[F. No. 6/1/Tariff/96/Vol-IV]

RAKESH KACKER, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published vide No. S. O. 251 (E), dated 30th March, 1992 and subsequently amended vide No.—

- (1) S.O. 36 (E) dated the 19th January, 1994.
- (2) S. O. 605 (E), dated the 22nd August 1994
- (3) S. O. 39 (E), dated the 13th January, 1995
- (4) S. O. 167 (E), dated the 6th November, 1995
- (5) S. O. 151 (E), dated the 26th February, 1997